IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण और लक्ष्य को संविधान में भेदभाव की प्रथा पर रोक लगाने के लिए जोड़ा गया है ?

1) अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया और इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया।

2) सभी के लिए सरकारी नौकरी में खुली भर्ती प्रक्रिया।

3) बड़े या हाशिए पर रह रहे समुदायों के अनुसार नहीं, बल्कि सरकार पर सभी लोगों को समानता के अधिकार का एहसास कराने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई।

कोड:

(A) केवल 1

(B) 1 और 3

(C) 1 और 2

(D) सभी

उत्तर: C

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : समानता न केवल प्रस्तावना में निहित एक प्रमुख मूल्य है, बल्कि संविधान के भाग III में शामिल एक मौलिक अधिकार भी है। अन्य प्रमुख मूल्य न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व हैं। एक प्रथा के रूप में अस्पृश्यता का कार्य समानता की अवधारणा के खिलाफ है। यह भेदभाव का सबसे निकृष्ट रूप है। इस प्रकार अनुच्छेद 17 इसे सभी रूपों में पूरी तरह से समाप्त कर देता है। न्यायपालिका सहित सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सभी के लिए भर्ती के लिए अवसर प्रदान करके एक समान स्तर का समाज बनाने की जिम्मेदारी है। सरकार समय-समय पर महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों आदि को विशेष सुविधा देती है, इसलिए कथन 3 गलत है। (अनुच्छेद 15)

प्रश्न: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का क्या दायित्व हैं?

1) सरकार करों से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2) सरकार सभी हाशिए पर रह रहे लोगों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3) बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोड:

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(A) 1 और 2

(B) 2 और 3

(C) केवल 2

(D) सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या :: स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से 'सार्वजनिक सेवा' कहा जाता है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है। साथ ही, इन सेवाओं को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों को उस धन से प्राप्त किया जाता है जिसे हम जनता, करों के रूप में सरकार को भुगतान करते हैं। इसलिए, ऐसी सुविधाएं सभी के लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि यह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ मुफ्त या कम लागत पर उपलब्ध कराने के लिए है, ताकि गरीब भी इलाज की तलाश कर सकें। सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य टीबी, मलेरिया, पीलिया, हैजा जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करना है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी पहल और इससे जुड़े संविधान का मूल मूल्य गलत तरीके से जुड़ा है / है?

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

1) सरकार को सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि और उद्योग के स्वामित्व को विनियमित करना चाहिए। -- प्रस्तावना के तहत समानता का सिद्धांत।

2) सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। - प्रस्तावना के तहत समाजवादी सिद्धांत।

3) किसी को भी अपने साथी नागरिक को नीचा नहीं समझना चाहिए। - प्रस्तावना के तहत भाईचारे का सिद्धांत।

कोड:

(A) 1 और 2

(B) 2 और 3

(C) 1 और 3

(D) सभी

उत्तर: A)

व्याख्या : *सरकार को सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि और उद्योग के स्वामित्व को विनियमित करना चाहिए - प्रस्तावना के तहत समाजवादी सिद्धांत।

* सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।- - प्रस्तावना के तहत समानता का सिद्धांत।

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है?

1) आवासीय क्षेत्र में एक भस्मक खोला गया है: अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

2) एड्स से पीड़ित होने के कारण एक शिक्षक को स्कूल से निकाल दिया गया है : अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है ।

3) कालीन उद्योग में 16 वर्ष के बच्चे को रोजगार देना : अनुच्छेद 21-A का उल्लंघन करता है।

कोड:

(A) 1 और 2

(B) 2 और 3

(C) 1 और 3

(D) सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या : अनुच्छेद 21 में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है |

अनुच्छेद 21-ए में शिक्षा का अधिकार शामिल है

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार

अनुच्छेद 15 - भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद 16 - रोजगार का समान अवसर|

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से मेल खाता है / हैं ?

1) पूर्वाग्रह - का अर्थ है अन्य लोगों को पूर्व-निर्धारित राय के माध्यम से या तो अनुकूल या प्रतिकूल मानना।

2) रूढ़ियाँ - का अर्थ है दूसरों को उनके धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर एक विशेष मानदंड में तय करना।

3) भेदभाव - पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी मानसिकता का कार्य का भाग है।

कोड:

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 2 और 3

(D) सभी

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उत्तर: D) (D)

व्याख्या :: पूर्वाग्रह और रूढ़ि दोनों ही एक लोकतांत्रिक समाज के लिए हानिकारक हैं। ये समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास को रोकते हैं; विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के परस्पर क्रिया को रोकना और प्रस्तावना में निहित मूल मूल्यों के विरुद्ध कार्य करना।

प्रश्न: जनहित याचिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) जनहित याचिका संविधान का एक स्पष्ट प्रावधान है जिसका उच्चतम न्यायालय पालन करता है।

2) सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

3) यह किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति देता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) 2 और 3

(C) 1 और 3

(D) सभी

उत्तर: (B)

व्याख्या :: संविधान में PIL का कोई उल्लेख नहीं है , हालांकि यह अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) से पता लगाया जा सकता है। जनहित याचिका की संकल्पना प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है।

प्रश्न: भारतीय समाज में आदिवासियों के हाशिए पर जाने का क्या कारण है?

1) आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरकार द्वारा चल रहे विकासात्मक मॉडल ।

2) अनोखी संस्कृति और लोगों में एकीकरण की कमी।

3) आदिवासी क्षेत्रों में व्यापारियों और साहूकारों का प्रवेश।

4) वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण।

कोड:

(A) 1, 2 और 3

(B) 2, 3 और 4

(C) केवल 3

(D) सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या :: आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे विकास मॉडल आदिवासी हितों में नहीं है, बल्कि यह आदिवासियों को उनके सामुदायिक संसाधनों से वंचित करता है। आदिवासी संस्कृति से जुड़े पूर्वाग्रहों से उन्हें बहुत नुकसान होता है। यह उन्हें हाशिए पर ले जाता है। व्यापारी और साहूकार आमतौर पर शोषणकारी व्यवसाय में शामिल होते हैं। वन पर नियंत्रण उन्हें उनकी आजीविका से वंचित करता है, जिससे वे आर्थिक रूप से हाशिए पर जाते जा रहे हैं।

प्रश्न: एक संवैधानिक संशोधन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) यदि संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी एक सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तो बिल लैप्स/कालातीत हो जाएगा।

2) निजी सदस्य द्वारा संवैधानिक संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) दोनों

(D) कोई नहीं

उत्तर: (A)

प्रश्न: एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है ?

(A) मौलिक कर्तव्य

(B) राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत

(C) मौलिक अधिकार

(D) प्रस्तावना

उत्तर: (B)

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करता है।

"राज्य इसके लिए प्रयास करेगा -

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें।
- एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान ; तथा

मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना।

प्रश्न: आनुपातिक न्याय के सिद्धांत में शामिल हैं:

(A) इस सिद्धांत में आवश्यक प्रयासों और कौशल और शामिल खतरे के आधार पर विभिन्न कार्यों को अलग-अलग रूप से पुरस्कृत करना शामिल है।

(B) इस सिद्धांत में लोगों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर पुरस्कार और कर्तव्यों का वितरण शामिल है।

(C) यह लोगों के साथ समान व्यवहार करने के सिद्धांत को इंगित करता है।

(D) यह लोगों के जाति और लिंग के प्रति समान रूप से व्यवहार करने के सिद्धांत को इंगित करता है।

उत्तर: (A)

व्याख्या : आनुपातिक न्याय: यह सिद्धांत लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और गुणवत्ता के अनुपात में पुरस्कृत करने का संकेत देता है। यह विभिन्न नौकरियों को अलग-अलग प्रयासों और आवश्यक कौशल और शामिल खतरे के आधार पर पुरस्कृत करने के लिए है। इस प्रकार, आनुपातिकता समान उपचार के सिद्धांत को संतुलन प्रदान करती है। एक सर्जन और एक वास्तुकार के लिए इनाम और मुआवजा उनकी नौकरी में आवश्यक कौशल के अनुसार भिन्न होता है।

प्रश्न: सिटीजन/नागरिक चार्टर नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी करने की सुविधा के लिए एक उपकरण है। सिटीजन चार्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है / हैं?

1) यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है इस प्रकार गैर-न्यायोचित है।

2) उपभोक्ता मामलों के विभाग चार्टर्स के निर्माण और कार्यान्वयन के साथ-साथ उनके मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

3) 'मॉडल के उपयोगकर्ताओं की बाध्यता को भारतीय मॉडल में जोड़ा गया है जबकि यह यूके मॉडल में अनुपस्थित है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें :

(A) 1 और 3

(B) 2 और 3

(C) केवल १

(D) सभी

उत्तर A: (A)

व्याख्या : नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है और इसलिए, गैर- न्यायोचित है। हालांकि, यह संगठन और उसके ग्राहकों की प्रतिबद्धताओं के साथ निर्दिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समय सीमा आदि के साथ नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा के लिए एक उपकरण है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, मूल्यांकन के साथ-साथ चार्टर्स के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। नागरिक चार्टर के निर्माण में उपभोक्ता संगठनों, नागरिक समूहों और अन्य हितधारकों को शामिल करने पर जोर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक चार्टर उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न :) अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए अध्यक्ष और प्रक्रिया, जो कि एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत पालन की जाएगी , निम्नलिखित संसदीय समिति में से किस समिति के मुद्दे को संदर्भित करती है ?

(A) व्यापार सलाहकार समिति

(B) विशेषाधिकार समिति

(C) याचिका समिति

(D) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

उत्तर: बी

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में न्यायिक समीक्षा लागू होती है?

1) विरोधी दलबदल कानून के तहत अध्यक्ष/सभापति द्वारा किए गए निर्णय।

2) राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य विधानसभा को निलंबित करने का राष्ट्रपति का निर्णय।

3) विधायिकाओं को दिया गया विशेषाधिकार।

कोड:

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(A) केवल 2

(B) 2 और 3

(C) 1 और 2

(D) सभी

उत्तर: डी

संविधान कहता है कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें संसद के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की गई है। इनमें दलबदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्षों द्वारा किए गए निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा, हाल ही में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला किया कि विधायकों का विशेषाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है| राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य विधानसभा को निलंबित करने का राष्ट्रपति का निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस मामले को पृथक्करण की शक्ति के उल्लंघन के तहत रखा जा सकता है ?

1) शत्रु संपत्ति अध्यादेश का पुन: प्रख्यापित ।

2) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीजल कारों पर उपकर लगाना।

3) सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य करना।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

कोड:

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) केवल 3

(D) सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या : शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन:

- **अध्यादेश - कार्यकारी बनाम विधायी।**
- **डीजल कारों पर उपकर - कार्यकारी बनाम न्यायपालिका।**
- **राष्ट्रगान बजाना - कार्यकारी बनाम न्यायपालिका।**

प्रश्न: सोशल ऑडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) यह स्थानीय, सामाजिक और उत्पादक सेवाओं के लाभार्थियों और प्रदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करता है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

2) यह स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

3) मनरेगा और स्वच्छ भारत अभियान के मामले में निरंतर सार्वजनिक सतर्कता के साधन के रूप में सामाजिक ऑडिट अनिवार्य है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) 1 और 3

(C) 1 और 2

(D) सभी

उत्तर: (C)

व्याख्या : सामाजिक अंकेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को सशक्त किया जाता है साथ ही योजनाओं और कार्यक्रम के अंतिम लाभार्थियों को भी | स्थानीय संगठन और सामाजिक संगठन की सामाजिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए मनरेगा को लेखा अंकेक्षण द्वारा सशक्त बनाया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण सरकार और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाते हैं, खासकर उन लोगों द्वारा जो प्रभावित होते हैं|

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

• गतिविधि के लाभार्थी, ऑडिट किए जाते हैं। पंचायत का कोई भी निवासी सामाजिक अंकेक्षण कर सकता है जो ग्राम सभा का हिस्सा है। सोशल ऑडिट के कुछ मूल उद्देश्यों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- स्थानीय विकास के लिए उपलब्ध जरूरतों और संसाधनों के बीच भौतिक और वित्तीय अंतराल का आकलन करना।

- लाभार्थियों और स्थानीय सामाजिक और उत्पादक सेवाओं के प्रदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना।

- स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता में वृद्धि।

- हितधारकों के हितों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतिगत निर्णयों की जांच, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों की।

- सार्वजनिक सेवाओं तक समय पर पहुँच न पाने के हितधारकों के लिए अवसर लागत का अनुमान।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से PRI अधिनियम के तहत स्वैच्छिक प्रावधान हैं ?

1) पंचायतों के चुनाव आयोजित करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करना।

2) किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।

3) किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) में आरक्षण प्रदान करना।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें :

(A) 1 और 2

(B) 2 और 3

(C) केवल 3

(D) सभी

उत्तर: (C)

व्याख्या : 73 वें संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान :

- अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर पड़ने वाले विभिन्न स्तरों पर संसद के सदस्यों (दोनों सदनों) और राज्य विधानमंडल (दोनों सदनों) को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना
- किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण प्रदान करना।
- स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए पंचायतों को अधिकार प्रदान कर सशक्त करना।
- पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, अर्थात उन्हें कर, शुल्क, टोल वसूलना, एकत्र करने की शक्ति प्रदान करना।

73 वें संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान:

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

- एक गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
- गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना।
- गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव।
- मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव।
- पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- तीनों स्तरों पर पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण।

पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।

प्रश्न: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

2) इसके सदस्यों की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

3) यह खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर आदिवासी और कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय करता है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 और 2

(B) 2 और 3

(C) 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

व्याख्या : अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत् जारी वारंट से नियुक्त किया जाता है।

• इसके सदस्यों की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

• आयोग को एससी, ओबीसी और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करनी है और काम होने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना है।

• यह अनुसूचित नीति और अनुसूचित जनजातियों के विकास के व्यापक नीतिगत मुद्दों और स्तरों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

हालाँकि, उस समय तक, इसका कोई स्पष्ट संवैधानिक समर्थन नहीं था।

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी केंद्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियाँ हैं ?

1) यह भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को उपस्थिति होने को कह सकता है और उसको जाँच हेतु शपथ दिला सकता है।

2) सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों की तकनीकी ऑडिट।

3) सीवीसी सीबीआई को निर्देश दे सकता है कि वह संयुक्त सचिव के स्तर के किसी भी अधिकारी के खिलाफ और उसके ऊपर के अधिकारीयों से पूछताछ शुरू करें।

4. सीवीसी के पास लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक मामला और अनुशासनात्मक मामले दर्ज करने की शक्तियां हैं।

नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करें :

(A) 1, 2 और 3

(B) 1, 3 और 4

(C) 1 और 2

(D) कोई नहीं

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उत्तर: (C)

व्याख्या : CVC के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है |राष्ट्रपति, आदेश से, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त कार्यालय से हटा सकते हैं यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या ऐसे सतर्कता आयुक्त, जैसा भी मामला हो: एक दिवालिया घोषित किया जाता है; या उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक क्रूरता शामिल है; या अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में अपने कार्यकाल के दौरान संलग्न है; या, राष्ट्रपति की राय में, मन या शरीर की दुर्बलता के कारण कार्यालय में जारी रखने के लिए अयोग्य है; या ऐसे वित्तीय या अन्य ब्याज का अधिग्रहण किया है, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या एक सतर्कता आयुक्त के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित करने की संभावना है।

प्रश्न: नागरिक सेवा का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना है। नागरिक चार्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है?

1) सेवा की गुणवत्ता

2) विकल्प प्रदान करना

3) जवाबदेही

4. पैसे का मूल्य

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

(A) 1, 2 और 4

(B) 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या: नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो मानक, सेवाओं, सूचना, विकल्प और परामर्श, गैर-भेदभाव और पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और धन के लिए मानक के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिक से संगठन की अपेक्षाएं भी शामिल हैं। नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना है। मूल रूप से तैयार किए गए नागरिक चार्टर आंदोलन के छह सिद्धांत थे:

- गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार;

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

- विकल्प: जहां भी संभव हो वहां विकल्प प्रदान करना;

- मानकों: निर्दिष्ट करें कि क्या मानकों को पूरा करने के लिए क्या उम्मीद की जाए और कैसे कार्य करें;
- मूल्य: करदाताओं के पैसे में मूल्य जोड़ें;
- जवाबदेही: व्यक्तियों और संगठनों के प्रति जवाबदेह होना ; तथा
- पारदर्शिता: नियमों या प्रक्रियाओं या योजनाओं या शिकायतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

प्रश्न: भारत में, राजनीतिक दलों या उनके उम्मीदवारों द्वारा चुनाव और अन्य राजनीतिक अभियानों के लिए धन जुटाया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निम्नलिखित में से किस संस्था को राजनीतिक दलों में योगदान करने की अनुमति है?

1) व्यक्तिगत

2) निजी कंपनियाँ

3) भारत में विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां

कोड:

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(A) केवल 1

(B) 2 और 3

(C) 1 और 2

(D) सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या : भारत में, चुनाव या अन्य राजनीतिक अभियानों को वित्त देने के लिए राजनीतिक दलों या उनके उम्मीदवारों द्वारा धन जुटाया जाता है। जनप्रतिनिधित्व कानून1951 के तहत, व्यक्तियों और कंपनियों (एक सरकारी कंपनी के अलावा) को राजनीतिक दलों में योगदान करने की अनुमति है। हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी को दिए गए योगदान की मात्रा पर कोई सीमा नहीं है, वहीँ कॉर्पोरेट योगदान विनियमित हैं। कंपनियां तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 7.5 प्रतिशत अधिकतम दान कर सकती हैं।

प्रश्न: दबाव समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) चुनाव: सार्वजनिक अधिकारियों को उनकी रुचि की नीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए राजी करना।

2) पैरवी: सार्वजनिक कार्यालय के व्यक्तियों में जो उनके हितों के पक्ष में हैं।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

3) प्रचार: जनता की राय को प्रभावित करना।

4) घेराव : नियोक्ता को एक विशेष स्थान पर सीमित करना और उन्हें अपने नियमित काम को न करने देना।

उपर्युक्त में से कौन सी विधि सही है/ हैं ?

(A) 3 और 4

(B) 1, 2 और 3

(C) 2, 3 और 4

(D) सभी

उत्तर: (A)

व्याख्या : विभिन्न विधियाँ हैं:

- निर्वाचन: सार्वजनिक कार्यालय में उन व्यक्तियों को जो उनके हितों का पक्ष लेते हैं।
- पैरवी: सार्वजनिक अधिकारियों को उनकी रुचि की नीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए राजी करना।
- प्रचार: जनता की राय को प्रभावित करना।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

• घेराव : इस तकनीक में दबाव समूह के सदस्य नियोक्ता को एक विशेष स्थान पर घेर लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं और और उन्हें अपने नियमित काम को न करने देना।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में सहकारी समिति के बारे में सही है/हैं ?

1) संविधान में सहकारी समितियों का कोई उल्लेख नहीं है।

2) सहकारी समितियों के समावेश, विनियमन और समापन के लिए प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं।

3) राज्य निर्वाचन आयोग सहकारी बोर्डों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है।

कोड:

(A) 1 और 2

(B) केवल 2

(C) केवल 3

(D) कोई नहीं

उत्तर: (D)

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : संविधान के भाग III में, शब्द "या यूनियनों" के बाद "सहकारी समितियाँ" शब्द जोड़ा गया था। भाग IV में एक नया अनुच्छेद 43B डाला गया था, जो कहता है: राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। "संविधान के भाग IXA के बाद, एक भाग IXB को राज्य बनाम केंद्र की भूमिकाओं को समायोजित करने के लिए जोड़ा गया था । यह स्वायत्त प्राधिकारियों की देखरेख में नियमित रूप से चुनाव कराने , कार्य और स्वतंत्र ऑडिट के लिए पांच साल का कार्यकाल सुनिश्चित करता है। गौरतलब है कि यह भी अनिवार्य किया गया है कि बोर्ड के भंग होने की स्थिति में नए का गठन छह माह के भीतर किया जाए।

प्रश्न: राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कार्यालय से हटा सकता है?

1) यदि वह किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में, अपने पद की अवधि के दौरान संलग्न है।

2) सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) दोनों

(D) कोई नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को कार्यालय से हटा सकता है:

- यदि उसे दिवालिया घोषित किया जाता है; या
- यदि उसे एक अपराध का दोषी ठहराया गया है (जो कि केंद्र सरकार की राय में) एक नैतिक भ्रष्टता शामिल है; या
- अगर वह अपने पद के कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न होता है ; या
- यदि वह (राष्ट्रपति की राय में), मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है ; या
- यदि उसने किसी तरह के वित्तीय या अन्य ब्याज का अधिग्रहण किया है, जिससे संभवतः उसके आधिकारिक कार्यों को प्रभावित करने की संभावना है।

इनके अतिरिक्त, राष्ट्रपति सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को भी हटा सकते हैं। हालांकि, इन मामलों में, राष्ट्रपति को इस मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजना होगा। अगर सुप्रीम

कोर्ट, जांच के बाद, हटाने के कारण को बताता है और सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। उसे दुर्व्यवहार का दोषी माना जाता है, यदि वह:

• केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध या समझौते में जुड़ा या इच्छुक है , या

• इस तरह के अनुबंध या समझौते के लाभ में या किसी भी सदस्य के रूप में या किसी निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाले किसी लाभ या उत्सर्जन में किसी भी तरह से भाग लेता है ।

प्रश्न: भारत में चुनाव कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन-से रिटर्निंग ऑफिसर के कार्य हैं?

1) रिटर्निंग ऑफिसर को संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से चुनाव आयोग द्वारा नामित किया जाता है।

2) निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाती है।

3) चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं।

4. रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की वापसी स्वीकार करता है और अंतिम सूची की घोषणा करता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:

(A) 1 और 3

(B) 2 और 4

(C) 1, 2 और 4

(D) सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या: प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में, एक अधिकारी को संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। हालांकि, एक अधिकारी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है। सभी नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं। पत्रों की जांच उसके द्वारा की जाती है और यदि वे क्रम में होते हैं, तो उसे उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं। वह उम्मीदवारों की वापसी को भी स्वीकार करता है और अंतिम सूची की घोषणा करता है। वह सभी मतदान केंद्रों की देखरेख करता है, मतों की गिनती उसकी देखरेख में की जाती है और अंतिम परिणाम उसके द्वारा घोषित किया जाता है। वास्तव में, रिटर्निंग अधिकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के कुशल और निष्पक्ष आचरण का समग्र प्रभारी होता है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस मामले में जनहित याचिका दायर की जा सकती है?

(A) आकस्मिक मजदूरों का शोषण और मजदूरी का भुगतान न होना।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(B) SC या ST से संबंधित व्यक्तियों का उत्पीड़न।

(C) दंगा पीड़ितों की याचिकाएँ।

(D) उपरोक्त सभी।

उत्तर: डी

जनहित याचिका एक ऐसा उपकरण है जो लोक कर्तव्य को लागू करने और संवैधानिक कानून या कानूनी प्रावधानों के पालन की मांग करता है। इस तरह के मुकदमे केवल एक सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए, एक सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने में या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि याचिका व्यक्तिगत लाभ या निजी मकसद के लिए या अन्य बाहरी विचार क्षेत्र के लिए नहीं है बल्कि सार्वजनिक हित में महत्वपूर्ण हो।

आम तौर पर जनहित याचिका में शामिल मामले हैं:

- बंधुआ मजदूर मामले।
- उपेक्षित बच्चों के मामले
- आकस्मिक मजदूरों का शोषण और उनकी मजदूरी का भुगतान न करना (व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर)।
- सह-ग्रामीणों या पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के उत्पीड़न या यातना के मामलों।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

• पारिस्थितिक संतुलन के पर्यावरण प्रदूषण की गड़बड़ी, ड्रग्स खाद्य पदार्थों की मिलावट, विरासत और संस्कृति के रखरखाव, प्राचीन वस्तुएँ, वन और वन्य जीवन से संबंधित मामले।

• दंगा पीड़ितों से याचिकाएँ |

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण हो सकता है?

1) यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है।

2) केंद्र उन विषयों की सूची को बदल सकता है जिन पर राज्यों की सहमति के बिना भी कर लगाने की शक्ति है।

3) केंद्र सरकार को राज्य की सहमति के बिना AFSPA, 1958 के तहत किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने का अधिकार है।

कोड:

(A) 1 और 3

(B) केवल 2

(C) केवल 3

(D) सभी

उत्तर: A

संविधान के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो समय आ गया है जब राज्य मशीनरी संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है और केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है।

संविधान के अनुसार, यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो समय आ गया है जब राज्य मशीनरी संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है और केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है।

केंद्र उन विषयों की सूची को नहीं बदल सकता है जिन राज्यों में राज्यों की सहमति के बिना भी कर लगाने की शक्ति है। इसे राज्य के आधे विधायकों की सहमति की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार को राज्य की सहमति के बिना AFSPA, 1958 के तहत किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने का अधिकार है।

प्रश्न: एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है?

(A) यह पार्टियों के बजाय व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए वोट डालने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार "बर्बाद वोट" को कम करता है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(B) परिणामों को गिनने की प्रक्रिया को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की तुलना में अधिक समय लगता है।

(C) एक ही पार्टी के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर आंका जा सकता है।

(D) यह सामरिक/ रणनीतिक मतदान को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि बहुत से मतदाता उस उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं जिसे वे सबसे अधिक पसंद करते हैं।

उत्तर: D

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के धर्मतंत्र रूप की मुख्य विशेषता नहीं है?

(A) धर्म और राज्य के बीच कोई अलगाव नहीं है।

(B) भूमि के नियम धार्मिक मान्यता से तय होते हैं।

(C) धार्मिक(ईश्वरतंत्र संबंधी/दैवीय) समाज प्रकृति में अधिनायकवादी हैं।

(D) धार्मिक समाज अधिक अच्छे लोगों पर केंद्रित है इसलिए लोगों की राय निर्णय लेने में ली जाती है।

उत्तर: (D)

व्याख्या : एक धार्मिक समाज के नागरिकों को इस तथ्य के साथ होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की राय को महत्व नहीं दिया जाएगा। एक धार्मिक समाज का जोर अधिक से अधिक अच्छे पर केंद्रित है |

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के समाजवादी सिद्धांत हैं?

1) एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए।

2) पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए।

3) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना।

4) गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके गलत उत्तर का चयन करें

(A) 1 और 4

(B) 2 और 3

(C) सभी

(D) 1, 2 और 4

उत्तर: (B)

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : गांधीवादी सिद्धांत: ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा दी गई पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके कुछ विचारों को निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था।

उन्हें पूरा करने हेतु राज्य को आवश्यकता है:

• एससी, एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए (अनुच्छेद 46)।

•• गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए और उनकी नस्लों में सुधार करना (अनुच्छेद 48)।

समाजवादी सिद्धांत

ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। वे एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और कल्याणकारी राज्य के लिए मार्ग निर्धारित करना है।

वे राज्य को निर्देशीत करते हैं:

• उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 ए)।

• पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए (अनुच्छेद 47)।

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त संवैधानिक उपकरण हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से हैं?

1) पूर्वोत्तर परिषद।

2) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद।

3) परिवहन विकास परिषद।

4.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें :

(A) 1 और 4

(B) 3 और 4

(C) 2, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (D)

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : गैर-संवैधानिक सलाहकार निकायों में राष्ट्रीय एकता परिषद, 10 केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, स्थानीय सरकार और शहरी विकास की केंद्रीय परिषद , क्षेत्रीय परिषद, 11 उत्तर-पूर्वी परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद , केंद्रीय परिषद होम्योपैथी, केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आदि शामिल हैं ।

प्रश्न: प्रस्तावना में उल्लिखित 'न्याय' का विचार तीन अलग-अलग रूपों में - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है को मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है | निम्नलिखित में से किस स्रोत से इन तीनो विचारों को उधार लिया गया है?

(A) अमेरिका का संविधान

(B) रूसी क्रांति

(C) फ्रांसीसी क्रांति

(D) ब्रिटिश संविधान

उत्तर: (B)

व्याख्या : भारतीय संविधान में न्याय का विचार जो तीन रूपों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप देता है , रूसी क्रांति (1917) से लिया गया है। 'न्याय' शब्द तीन अलग-अलग रूपों-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, को प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त करता है।

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है/ हैं ?

संघ राज्य क्षेत्र : गठन का कारण

1) अंडमान और निकोबार - सामरिक महत्व

2) पुदुचेरी - विशिष्ट संस्कृति

3) चंडीगढ़ - प्रशासनिक तौर पर

4) दमन और दीव - जनजातीय विचार

कोड:

(A) 1 और 2

(B) 2 और 3

(C) केवल 4

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : ब्रिटिश राज के बाद से विदेशी कब्जे के कारण सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए दमन और दीव का मतलब है।

प्रश्न: कौन से संसदीय शब्द गलत हैं?

(A) " अनिश्चितकाल के लिए स्थगन -" किसी भी निश्चित तिथि के बिना सदन के बैठक का विघटन।

(ख) "कास्टिंग वोट" -किसी मामले पर वोटों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा वोट डाला जाना।

(C) "मतपत्र" - बहुत से ड्रा के माध्यम से एक से अधिक नोटिस की अंतर से प्राथमिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया।

(D) " क्रासिंग द फ्लोर " - निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों की सापेक्ष पूर्वनिर्धारितता को निर्धारित करने के लिए लागू एक विधि।

उत्तर: डी

" क्रासिंग द फ्लोर " - सदन और सभापति को संबोधित करने वाले सदस्य के बीच गुजरना जिसे संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है।

प्रश्न: भारतीय संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार कायम रखती है -

1) सभी व्यक्तियों की समानता

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

2) व्यक्ति की गरिमा

3) बड़े स्तर पर सार्वजनिक हित

4) राष्ट्र की एकता

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) 1, 2 और 4

(C) 3 और 4

(D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: D

o भारतीय संविधान का भाग III सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 -18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29-30)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के दी जाती है। वे अनुच्छेद 14 से 18 के माध्यम से सभी व्यक्तियों की समानता को बनाए रखते हैं, अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा और मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों के माध्यम से व्यापक राष्ट्र जनहित और एकता को सुरक्षित करना।

प्रश्न: अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) यह केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों तक विस्तारित है।

2) यह अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/ हैं ?

(A) केवल 1

(B) 2 केवल

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

कथन 1 सही नहीं है: अनुच्छेद 29 यह प्रदान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों की किसी भी हिस्से की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसके संरक्षण का अधिकार होगा।इस प्रकार, यह दोनों धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों के लिए आवश्यक नहीं है। इसका कारण है कि अनुच्छेद में नागरिकों के वर्ग शब्द का उपयोग करना जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।

o कथन 2 सही नहीं है: अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।

प्रश्न: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी- बौद्धिक सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत है?

1) पूरे देश में समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के लिए।

2) आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

3) राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 3

(B) 1 और 2 केवल

(C) 2 और 3 केवल

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: डी

डीपीएसपी में शामिल उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत हैं:

- पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाना (अनुच्छेद 44)।
- सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए जब तक कि वे छह वर्ष की आयु (अनुच्छेद 45) को पूरा नहीं करते।
- आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना (अनुच्छेद 48)।
- पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन और वन्य जीवन की रक्षा के लिए (अनुच्छेद 48 ए)।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

- कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है (अनुच्छेद 49)।
- राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना (अनुच्छेद 50)।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने के लिए, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए (अनुच्छेद 51)।
-

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा/से भारत के संविधान के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं ?

1) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।

2) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना।

3) हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1 और 3

(B) 2 केवल

(C) 2 और 3 केवल

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: D

कथन 1 सही है:

अनुच्छेद 51 a (c) के अनुसार, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे।

o कथन 2 सही है: अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि यह राज्य का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक हित की वस्तु की रक्षा करे जो राष्ट्रीय महत्व का हो।

o कथन 3 सही है: अनुच्छेद 51 ए (एफ) के अनुसार, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और संरक्षित करे।

प्रश्न: "वे भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन्स से मिलते-जुलते हैं, जिन्हें बाद में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। वे न तो कोई कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं और न ही उनके उल्लंघन के खिलाफ कानूनी उपाय हैं। ' उपर्युक्त गद्यांश भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है?

(A) मौलिक कर्तव्य

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(B) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

(C) प्रस्तावना

(D) मौलिक अधिकार

उत्तर: B

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार के अधिनियम, 1935 में उल्लिखित निर्देशों के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं, बाद में उन्होंने वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया।

o डॉ. बीआर अंबेडकर के शब्दों में, निर्देशक सिद्धांत निर्देश के उपकरण की तरह हैं, जो गवर्नर-जनरल और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार के उपनिवेशों के राज्यपालों को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जारी किए गए थे। कहा जाता है कि निर्देशक सिद्धांत निर्देशों के उपकरण(the instrument of instructions) के लिए केवल एक और नाम है। अंतर केवल इतना है कि वे विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश हैं'।

o DPSP न तो कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है और न ही कानूनी उपाय बनाता है। हालांकि, वे राज्य के कार्यान्वयन के लिए नैतिक दायित्व बनाते हैं।

प्रश्न: भारत में निवारक निरोध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

1) गिरफ्तारी के आधार पर बंदी को सूचित करना अनिवार्य है।

2) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है or हैं?

(A) केवल 1

(B) 2 ही

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: डी

अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को संरक्षण देता है।

o निरोधात्मक निरोध अनुच्छेद 22 में उल्लिखित पाया जाता है और इसका अर्थ है बिना किसी अदालत द्वारा किसी भी व्यक्ति को मुकदमे की सजा और हिरासत में रखा जाना। इसका उद्देश्य निकट भविष्य में उसे अपराध करने से रोकना है।

o अनुच्छेद 22 का पहला भाग एक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार देता है जो एक साधारण कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में है:

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

- गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- कानूनी जानकर द्वारा परामर्श और बचाव का अधिकार।
- यात्रा समय को छोड़कर, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
- 24 घंटे के बाद रिहा करने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देता।
- ये सुरक्षा संबंधी बातें किसी विदेशी या किसी निरोधात्मक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

लोग जो एक निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए हैं उनकी सुरक्षा निम्नलिखित है:

- जब तक कोई सलाहकार बोर्ड विस्तृत निरोध के पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता तब तक किसी व्यक्ति की नजरबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती। बोर्ड एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने संविधान के अभिन्न अंग के रूप में निवारक नजरबंदी नहीं की है जैसा कि भारत में किया गया है।

प्रश्न: भारतीय संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 12 में परिभाषित निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा ?

1) संसद

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

2) पंचायत और नगरपालिका

3) वैधानिक प्राधिकरण

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1 और 2

(B) 2 और 3 ही

(C) 1, 2 और 3

(D) केवल 1 और 3

उत्तर: सी

o अनुच्छेद 12 के अनुसार, राज्य(state) में निम्नलिखित शामिल हैं: (A) भारत की सरकार और संसद, यानी केंद्र सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग। (B) राज्यों की सरकार और विधायिका, यानी राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग। (C) सभी स्थानीय प्राधिकरण, यानी नगरपालिका पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास इत्यादि (D) अन्य सभी प्राधिकरण, यानी वैधानिक या गैर- वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, SAIL, आदि।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

इस प्रकार, state को एक व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है ताकि इसकी सभी एजेंसियों को शामिल किया जा सके। यह इन एजेंसियों की कार्रवाई पर जिन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अदालतों में चुनौती दी जा सकती है।

o सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यहां तक कि एक निजी संस्था या राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाली एक एजेंसी अनुच्छेद 12 के तहत State के अर्थ में आती है।

प्रश्न: पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ।

1) इस अधिनियम के तहत, मवेशियों को केवल कृषि कार्यों के लिए खरीदा जा सकता है।

2) यह कुत्ते के प्रजनकों और मछलीघर की दुकान के मालिकों तक विस्तारित है ।

3) भारत का पशु कल्याण बोर्ड इसके तहत स्थापित किया गया था।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) 2 और 3 ही

(C) 1 और 3 केवल

(D) 1, 2 और 3

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उत्तर: D

केंद्र सरकार ने मवेशियों में व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजारों का विनियमन) नियम, 2017 को क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अधिसूचित किया है। मुख्य प्रावधान देश भर के पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध है। मवेशियों को अब केवल कृषि प्रयोजनों के लिए खरीदा जा सकता है। इसलिए, कथन 1 सही है।

o पशुओं के लिए क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960:

- यह जानवरों पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा के प्रवाह को रोकने के लिए लागू किया गया था।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत का पशु कल्याण बोर्ड, इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसलिए, कथन 3 सही है।

• यह जानवरों के बाजारों, कुत्तों के प्रजनकों, मछलीघर और पालतू मछली की दुकान के मालिकों को नियंत्रित करता है। इसलिए कथन 2 सही है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा 'चेक और बैलेंस' की प्रणाली के पीछे एक उद्देश्य है?

(A) यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

(B) इसका उद्देश्य सरकार और प्रशासन में विविध सामाजिक समूहों को स्थान देना है।

(C) यह सुनिश्चित करता है कि हित समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव डाले।

(D) यह संघ में संघ सरकार की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को सीमित करता है।

उत्तर: ए

सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति साझा की जाती है। हम इसे शक्ति के क्षैतिज वितरण भी कहते हैं क्योंकि यह विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है। ऐसा अलगाव यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। प्रत्येक अंग दूसरों की जाँच करता है। इससे विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति संतुलन कायम होता है। भले ही मंत्री और सरकारी अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं, वे संसद या राज्य विधानसभाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह, हालांकि न्यायाधीशों कार्यकारी या विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के कामकाज की जांच कर सकते हैं। इस व्यवस्था को जांच और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है।

प्रश्न: अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत होता है तो न्यायालय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को किसी भी कानून को अमान्य करने के लिए लागू करते हैं?

(A) पार्थक्य का सिद्धांत(Doctrine of Severability)

(B) 'तत्व एवं सार' के सिद्धांत

(C) छद्मता का सिद्धांत

(D) निहित शक्ति का सिद्धांत

उत्तर: ए

o पार्थक्य का सिद्धांत : एक कानून केवल उस सीमा तक अमान्य हो जाता है, जिस तक वह मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है। तो केवल कानून के उस हिस्से को अमान्य घोषित किया जाएगा जो असंगत है, और बाकी कानून बने रहेंगे। हालाँकि, इस बिंदु पर न्यायालयों द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि कानून का अमान्य हिस्सा अलग कर दिया जाएगा और यदि वास्तव में यह पार्थक्य योग्य है, तो अमान्य घोषित किया जाता है, अर्थात यदि अमान्य भाग को अलग करने के बाद वैध भाग विधायिका के इरादे को प्रभावित करने में सक्षम है। , तभी यह जीवित रहेगा, अन्यथा अदालत पूरे कानून को अमान्य घोषित करेगी। इसे पार्थक्य का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

o निहित शक्ति का सिद्धांत: यह एक कानूनी सिद्धांत है जो बताता है कि, सामान्य रूप से, एक विधायी निकाय या संगठन के अधिकार और कर्तव्य उसके कार्यों और उद्देश्यों से निर्धारित होते हैं जैसा कि उसके संविधान या चार्टर में निर्दिष्ट है और व्यवहार में विकसित किया गया है।

'तत्व एवं सार' के सिद्धांत: तत्व का अर्थ है 'वास्तविक प्रकृति' या 'सार' और सार का अर्थ है एक घटना के लिए आवश्यक प्रकृति। इस प्रकार, 'तत्व एवं सार' का सिद्धांत एक क़ानून की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने से संबंधित है। इस सिद्धांत का व्यापक रूप से यह तय करते समय उपयोग किया जाता है कि क्या कोई राज्य संविधान के संघ सूची में

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उल्लिखित किसी विषय को शामिल करने के लिए अपने अधिकारों के भीतर है या नहीं। इस सिद्धांत के पीछे मूल विचार यह है कि राज्य द्वारा बनाया गया एक अधिनियम या एक प्रावधान वैध है यदि अधिनियम की वास्तविक प्रकृति या प्रावधान एक विषय के बारे में है जो राज्य सूची में आता है।

o छद्मता का सिद्धांत: यह संबंधित विधानमंडलों की विधायी क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण है। सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा लागू किया जा सकता है। यह अधीनस्थ विधानों पर लागू नहीं है।

प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान की गई विधि के समक्ष समानता की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) यह समान परिस्थितियों में सभी को समान अधिकार देने की एक सकारात्मक अवधारणा है।

2) यह भारतीय संविधान के लिए एक अवधारणा है।

3) समानता के अधिकार के तहत सकारात्मक भेदभाव प्रदान किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/ हैं ?

(A) केवल 1

(B) 2 ही

(C) 2 और 3 ही

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: A

o अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा।

o कथन 1 सही है और 2 सही नहीं है: कानून की समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है।

यह बताता है: (A) किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार का अभाव, (B) सामान्य कानून अदालतों द्वारा प्रशासित भूमि के सामान्य कानून के लिए सभी व्यक्तियों की समान अधीनता,और (C) कोई व्यक्ति (चाहे वह अमीर हो या गरीब, उच्च या निम्न, आधिकारिक या गैर-आधिकारिक) कानून से ऊपर नहीं है। यह कुछ हद तक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और सामान्य कानून के लिए सभी वर्गों की समान अधीनता को प्रभावित करती है।

o अनुच्छेद 16: सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार के मामलों में अधिमान्य उपचार। इसलिए, अनुच्छेद 16 के तहत सकारात्मक भेदभाव प्रदान किया जाता है जबकि अनुच्छेद 14 के तहत नहीं अर्थात कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षणमें नहीं | इसलिए, स्टेटमेंट 3 सही नहीं है।

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: प्रस्तावना में 'समानता' शब्द संविधान में किन प्रावधानों के द्वारा पूरक है ?

1) लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे (अनुच्छेद 326)।

2) अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17)।

3) उपाधियों का उन्मूलन (अनुच्छेद 18)

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1

(B) 1 और 2 ही

(C) 3 ही

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: डी

o EQUALITY 'शब्द का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकार का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

o यह प्रावधान समानता के तीन आयामों को स्वीकार करता है - नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। मौलिक अधिकार नागरिक समानता सुनिश्चित करते हैं:

- कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
- सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
- अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17)। इसलिए, कथन 2 सही है।
- उपाधियों का उन्मूलन (अनुच्छेद 18)। इसलिए, कथन 3 सही है।

संविधान में दो प्रावधान हैं जो राजनीतिक समानता प्राप्त करना चाहते हैं:

किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा (अनुच्छेद 325)। लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। (अनुच्छेद 326)। इसलिए, कथन 1 सही है।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक समानता सुनिश्चित की जाती है। अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के समान अधिकार प्रदान करता है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से संपत्ति के अधिकार के निहितार्थ भारत में कानूनी अधिकार हैं?

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

1) निजी संपत्ति कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ संरक्षित है न कि विधायी कार्रवाई।

2) राज्य द्वारा इसके अधिग्रहण के मामले में मुआवजे के अधिकार की गारंटी नहीं है।

3) पीड़ित व्यक्ति सीधे इसके उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1

(B) 1 और 2 ही

(C) 2 और 3 ही

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: D

o 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने भाग III से अनुच्छेद 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसने संपत्ति के अधिकार (Right to Property ') शीर्षक के तहत एक नया अनुच्छेद 300A डाला।

o कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार (मौलिक अधिकारों से अलग) के निम्नलिखित निहितार्थ हैं:

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

यह संसद के एक सामान्य कानून द्वारा संवैधानिक संशोधन के बिना बंद, निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।

यह कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधायी कार्रवाई के खिलाफ नहीं।

♣ उल्लंघन के मामले में, पीड़ित व्यक्ति अपने प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 (राइट्स सहित संवैधानिक उपचार का अधिकार) के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या आवश्यकता के मामले में मुआवजे के अधिकार की कोई गारंटी नहीं।

प्रश्न: केंद्रीय सचिवालय के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों का एक समूह है।

2) इसका मुख्य कार्य नीतियों को लागू करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) 2 ही

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

o कथन 1 सही है: केंद्रीय सचिवालय में ऐसे विभाग या मंत्रालय होते हैं जिनके प्रशासनिक प्रमुख सचिव के रूप में नामित होते हैं और जिनके राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं। सचिवालय सामूहिक जिम्मेदारी के साथ एक एकल इकाई के रूप में कार्य करता है जैसा कि मंत्रिपरिषद के मामले में है। मौजूदा नियमों के तहत, प्रत्येक सचिवालय विभाग को किसी अन्य विभाग से परामर्श करने की आवश्यकता होती है जो किसी मामले को निपटाने से पहले संबंधित हो सकता है।

o कथन 2 सही नहीं है: भारत में केंद्रीय सचिवालय प्रणाली दो सिद्धांतों पर आधारित है:

(A) नीति निर्माण के कार्य को नीति कार्यान्वयन से अलग करने की आवश्यकता।

(B) कार्यकाल प्रणाली पर काम कर रहे अधिकारियों के कैडर को बनाए रखना सचिवालय प्रणाली के काम के लिए एक शर्त है। केंद्रीय सचिवालय सरकार की नीति बनाने वाली संस्था है और जब तक कि कुछ कार्य करने के लिए आधिकारिक एजेंसियों की कमी की आवश्यकता न हो, तब तक निष्पादन का कार्य नहीं करना है।

प्रश्न: छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(B) राष्ट्रपति को आदिवासी क्षेत्रों को संगठित और पुनर्गठित करने का अधिकार है।

(C) प्रत्येक स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र में नामित और निर्वाचित सदस्यों के साथ एक जिला परिषद है।

(D) जिला परिषदों को केवल राज्यपाल की सहमति से भू-राजस्व एकत्र करने का अधिकार है।

उत्तर: C

छठी अनुसूची के तहत संविधान में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। वे राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी के बाहर नहीं आते हैं क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में अधिकांश शक्तियां राज्यपाल के हाथों में हैं।इसलिए, विकल्प (A) सही नहीं है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। इस प्रकार, वह उन क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है या उसका नाम बदल सकता है या सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां हैं, तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। इसलिए, विकल्प (B) सही नहीं है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होता है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्य पाँच साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं (जब तक कि परिषद को पहले भंग नहीं किया जाता है) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद्प्रयंत तक पद धारण करते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है। इसलिए, विकल्प (C) सही है। जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व का आकलन करने और इकट्ठा करने और कुछ निर्दिष्ट करों को लगाने का

अधिकार है। यह उस स्थिति में है जब जिला परिषद गैर- आदिवासियों द्वारा धन उधार देने और व्यापार के नियंत्रण के लिए नियम बना रही है, ऐसे नियमों के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। इसलिए, विकल्प (D) सही नहीं है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ?

1) हिरासत में व्यक्ति।

2) सामूहिक आपदा के शिकार।

3) ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 3

(B) 1 और 2 ही

(C) 2 और 3 ही

(D) 1, 2 और 3

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उत्तर: डी

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NALSA) का गठन 5 दिसंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है (अधिनियम की धारा 12 में परिभाषित), और मामलों के शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना। भारत के मुख्य न्यायाधीश NALSA के मुख्य संरक्षक हैं जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यकारी-अध्यक्ष हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत पात्र व्यक्ति में शामिल हैं:

1) महिलाएं और बच्चे

2) SC or ST के सदस्य

3) औद्योगिक कामगार

4) सामूहिक आपदा, हिंसा का शिकार

5. दिव्यांग व्यक्तियों

6. हिरासत में व्यक्ति

7. ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) वह अपने कार्यकाल के दौरान किए गए अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में सभी सिविल कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्राप्त करता है।

2) पद की अवधि के दौरान अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

3) वह अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए सभी कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राप्त करता है।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) 2 और 3 ही

(C) 1, 2 और 3

(D) कोई नहीं

उत्तर: B

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

संविधान भारत के राष्ट्रपति को उनके आधिकारिक कृत्यों और व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में कुछ प्रतिरक्षाएं प्रदान करता है। ये हैं:

(A) आधिकारिक कृत्यों : राष्ट्रपति को उनके कार्यालय के कार्यकाल के दौरान या उसके बाद, उनके आधिकारिक शक्तियों और कर्तव्यों के प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि, महाभियोग के आरोपों की जांच के लिए राष्ट्रपति के आधिकारिक आचरण की संसद के किसी भी सदन द्वारा न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य निकाय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। इसलिए, कथन 3 सही है |

(ख) व्यक्तिगत कृत्य: राष्ट्रपति के खिलाफ उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है | यह प्रतिरक्षा केवल उनके कार्यालय के कार्यकाल की अवधि तक सीमित है और इससे आगे नहीं बढ़ती है। हालांकि, दो महीने की अग्रिम सूचना देने के बाद अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में पद के दौरान उनके खिलाफ नागरिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है और 2 सही है।

प्रश्न: 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू नहीं किया गया था ?

(A) "सशस्त्र विद्रोह " शब्द को "आंतरिक गड़बड़ी" के लिए प्रतिस्थापित किया।

(B) भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से में आपातकाल के संचालन को सीमित करने के लिए राष्ट्रपति को सक्षम किया गया।

(C) राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा केवल कैबिनेट से लिखित सिफारिश पर की जा सकती है।

(D) विशेष बहुमत से संसद के किसी भी सदन द्वारा आगे की निरंतरता के लिए आवधिक अनुमोदन।

उत्तर: B

1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित संशोधन किए: -

o इसने 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को 'आंतरिक गड़बड़ी' के लिए प्रतिस्थापित किया। इस प्रकार, 'आंतरिक गड़बड़ी' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना अब संभव नहीं है जैसा कि 1975 में हुआ था।

o मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपातकाल केवल कैबिनेट की सहमति पर घोषित किया जा सकता है, न कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर।

o आपातकाल की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए (मूल रूप से, संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि दो महीने थी)।

o संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर, आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है, और हर छह महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ बढ़ाया जा सकता है।

o आपातकाल के उद्घोषणा या उसकी निरंतरता को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए ,कि (A) उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत , और (ख) उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

o 1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को सीमित करने में सक्षम बनाया।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्पीकर के कार्यालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है?

1) उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है।

2) उनका वेतन भारत के समेकित कोष पर भारित होता है।

3) वह पहली बार में वोट नहीं दे सकता है लेकिन बराबरी होने पर मत डाल सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1 और 3

(B) 2 और 3 ही

(C) केवल 1 और 2

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: D

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

निम्नलिखित प्रावधान अध्यक्ष के कार्यालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं:

1. उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत (अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, न कि साधारण बहुमत (अर्थात, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत) द्वारा । निष्कासन के इस प्रस्ताव पर तभी विचार और चर्चा की जा सकती है जब उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। इसलिए, कथन 1 सही है।

2. उनका वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। उन्हें भारत के समेकित कोष पर भारित किया जाता है और इस प्रकार संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं किया जाता है। इसलिए, कथन 2 सही है।

3. उनके कार्य और आचरण की चर्चा और आलोचना लोकभासा में नहीं की जा सकती है, सिवाय एक प्रस्ताव के।

4. प्रक्रिया को विनियमित करने या व्यवसाय का संचालन करने या सदन में व्यवस्था बनाए रखने की उनकी शक्तियां किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।

5. वह पहली बार में वोट नहीं कर सकता। वह केवल एक टाई की स्थिति में एक वोट डाल सकते हैं। यह स्पीकर की स्थिति को निष्पक्ष बनाता है। इसलिए, कथन 3 सही है।

6. वरीयता के क्रम में उन्हें बहुत उच्च स्थान दिया जाता है। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सातवें स्थान पर रखा गया है। इसका मतलब है, उनके पास प्रधानमंत्री या उप प्रधान मंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में एक उच्च पद है।

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

प्रश्न: वित्तीय संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा लागू की जाती हैं ?

1) अनुदान-सहायता

2) ऋण मुक्ति

3) केंद्रीय कर और कर्तव्य

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1 और 3

(B) 2 ही

(C) 2 और 3 ही

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: A

वित्तीय संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नानुसार हैं : -

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

o राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा लागू किए जाने वाले: केंद्रीय कर और कर्तव्यों का वितरण और अनुदान इस श्रेणी में आते हैं।

o जिन्हें कार्यकारी आदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है: लाभ का साझा करना, पेट्रोलियम, ऋण में राहत, केंद्रीय सहायता का तरीका आदि ।

प्रश्न: अटल टिंकरिंग लैब मैराथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) यह छह अलग-अलग विषयगत क्षेत्रों में छह महीने की लंबी राष्ट्रव्यापी चुनौती है।

2) यह 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी छात्रों के लिए खुला है।

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1

B) 2 ही

C). दोनों 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (A) केवल 1

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

यह छह अलग-अलग विषयगत क्षेत्रों, स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट गतिशीलता और कृषि-तकनीक में छह महीने की लंबी राष्ट्रव्यापी चुनौती है। यह 18 वर्ष से कम आयु के सभी छात्रों के लिए खुला है। शीर्ष 30 नवाचारों के छात्रों को बौद्धिक संपदा, प्रभावी संचार, व्यावसायिक संपत्ति और उद्यमिता कौशल आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा |

अटल टिंकरिंग लैब मैराथन का आयोजन अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के अटल टिंकरिंग लैब्स और NITI Aayog द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र इनोवेटरों की पहचान करने के प्रयास में किया जा रहा

प्रश्न: राष्ट्रीय निष्ठा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय/शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।

2) यह एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षणों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से एक मिशन है।

3) मिशन सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों तक सीमित है।

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

A. 1 और 2 ही

(B) 2 और 3 ही

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

C).1 और केवल 3

D) 1, 2 और 3

उत्तर : (A) केवल 1 और 2

यह एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षणों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से एक मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य देश भर के सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों को शामिल करते हुए 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना है ,

- NishTHA- National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement (NISHTHA) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर मे शुरू की गई है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए) के कार्यान्वयन को रद्द करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।

a) आंध्र प्रदेश
b) मिजोरम
c) छत्तीसगढ़
d) असम

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उत्तर: : B

मिजोरम सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन को रद्द करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। संविधान के अनुच्छेद 371 (जी) के तहत, मिजोरम में एक विशेष प्रावधान है, जो भूमि के स्वामित्व से संबंधित संसद के सभी विधानों के लिए अनिवार्य है और राज्य में इसे लागू होने से पहले एक प्रस्ताव के माध्यम से राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया जाना है। राज्य सरकार ने संविधान के इस प्रावधान का उपयोग राज्य से एफआरए को रद्द करने हेतु एक प्रस्ताव पारित कर किया।

प्रश्न: प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) यह कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

2) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन निधि प्रबंधक और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

3) 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है।

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

a) 1 और 2 ही

b) 2 और 3 ही

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर : (D)

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है। रुपये की मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें 3000/- प्रदान किया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन निधि प्रबंधक होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रश्न: सोवा-रिग्पा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो अक्सर समाचार में दिखाई देते हैं::

1) यह भारत के दक्षिणी भाग में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है।

2) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा- रिग्पा (NISR) की स्थापना को मंजूरी दे दी है ।

3) सोवा- रिग्पा के सिद्धांत और व्यवहार अधिकांश " आयुर्वेद " के समान है ।

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

a) 1 और 2 केवल

b) 2 और 3 केवल

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर : (B)

यह भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। यह तिब्बत में उत्पन्न हुआ और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस जैसे देशों में प्रचलित है। सोवा- रिग्पा के सिद्धांत और व्यवहार का अधिकांश " आयुर्वेद " के समान है। माना जाता है कि तिब्बत के युथोग योंटेन गोनपो को सोवा रिग्पा का पिता माना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा- रिग्पा (NISR) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

प्रश्न: ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया किसकी एक पहल है:

a) विश्व आर्थिक मंच

b) यूएनडीपी

c) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

d) NITI Aayog

उत्तर : (c)

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक पहल है। भारत, दुनिया भर से सिद्ध और संभावित नवीन तकनीकों की एक संग्रह की पहचान करने, मूल्यांकन करने और उसे छोटा करने के उद्देश्य से और उसके बाद भारतीय निर्माण क्षेत्र में उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर रहा है जो टिकाऊ, नया व, आपदा प्रतिरोधी है। केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी) के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सर्विसेज अवास पोर्टल (CLAP) लॉन्च किया है। जीएचटीसी-भारत के तहत लाइटहाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए केंद्रीय आवास मामलों के मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही पोर्टल लॉन्च किया गया था।

प्रश्न: वाहन मिशन योजना 2026(AMP) के उद्देश्य हैं / हैं:

1) भारतीय मोटर वाहन उद्योग को "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम का इंजन बनने के लिए प्रेरित करना।

2) भारतीय मोटर वाहन उद्योग के शुद्ध निर्यात में कई गुना वृद्धि करने के लिए।

3) इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है or हैं?

a) 1 और 2 ही

b) 2 और 3 ही

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

ग) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर : (A) केवल 1 और 2

मोटर वाहन मिशन योजना 2026 के उद्देश्य में शामिल हैं: भारतीय मोटर वाहन उद्योग को "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम का इंजन बनने के लिए प्रेरित करना। भारतीय मोटर वाहन उद्योग को "कौशल भारत" कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाना। देश में हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित, कुशल और आरामदायक गतिशीलता को बढ़ावा देना,

दोनों सार्वजनिक और व्यक्तिगत परिवहन विकल्पों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सामर्थ्य पर नज़र रखना। भारतीय मोटर वाहन उद्योग के शुद्ध निर्यात में कई गुना वृद्धि करना।

उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी नियमों के लिए व्यापक और स्थिर नीति वितरण को बढ़ावा देना। एएमपी 2026 भारत सरकार और मोटर वाहन उद्योग की सामूहिक दृष्टि है, जहां मोटर वाहन उद्योग और ऑटो घटक उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को आकार और समग्र के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के संदर्भ में 2026 तक बनाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: विधायिका में 'तारांकित प्रश्न' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) यह वह है जिसमें एक सदस्य सदन में मंत्री के लिखित उत्तर की इच्छा रखता है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

2) संसद के 2019 के शीतकालीन सत्र में एक दिन में प्रश्नकाल के दौरान 20 से अधिक तारांकित प्रश्न उठाए गए, जो 1972 के बाद का रिकॉर्ड है।

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

(a) केवल 1

(b)2 ही

C.) दोनों 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (B)

तारांकित प्रश्न वह होता है, जिसके सदस्य सदन में मंत्री से मौखिक उत्तर की इच्छा रखते हैं तब उसे एक तारांकन चिह्न के साथ प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के प्रश्न का उत्तर सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के बाद हो सकता है।

प्रश्न: यूएनडीपी द्वारा एक त्वरक प्रयोगशाला के शुभारंभ के पीछे के उद्देश्य हैं:

(a) स्थायी आवास

b) बालिका शिक्षा

c) ग्रामीण विद्युतीकरण

d) प्रदूषण पर काम करना

उत्तर : (D)

UNDP ने प्रदूषण, पानी के मुद्दों पर काम करने के लिए भारत में त्वरक (एक्सेलेरेटर) लैब शुरू की। एक्सेलेरेटर लैब UNDP, जर्मनी और कतर द्वारा आज की 21 वीं सदी की जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नई पहल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) कार्यालय में रखी जाने वाली प्रयोगशाला ने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है। UNDP ने प्रदूषण, पानी के मुद्दों पर काम करने के लिए भारत में एक्सेलेरेटर लैब शुरू की।

प्रश्न: हाल ही में, ' YuWaah ' - जनरेशन अनलिमिटेड पहल समाचारों में देखी गई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया है:

a) जी 20

b) नीति आयोग

c) यूनिसेफ

d) युवा मामले का मंत्रालय

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उत्तर : (सी) यूनिसेफ

इसे यूनिसेफ ने लॉन्च किया है। यह निजी क्षेत्र, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों के साथ युवाओं को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य उनके सीखने और प्रशिक्षण में निवेश की तत्काल चुनौती से निपटना है ताकि वे काम की जटिल और तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार हों और सक्रिय और शामिल नागरिक बन सकें।

प्रश्न: रोटावायरस को अक्सर समाचारों में देखा जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1) यह दोहरे फंसे डीएनए वायरस का एक जीनस है।

2) यह पांच साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर दस्त और मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।

3) हाल ही में उपराष्ट्रपति ने नया रोटावायरस वैक्सीन - ROTAVAC5D लॉन्च किया है

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

a) 1 और 2 ही

b) 2 और 3 ही

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर : (B) 2 और 3 केवल

रोटावायरस पांच साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर दस्त और मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। यह हर साल कुल बाल मृत्यु दर के लगभग 10% के लिए जिम्मेदार है। रोटावायरस विष्टा-मौखिक मार्ग द्वारा, दूषित हाथों, सतहों और वस्तुओं के संपर्क के माध्यम से और संभवतः श्वसन मार्ग द्वारा प्रेषित होता है। वायरल दस्त अत्यधिक संक्रामक है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने नया रोटावायरस वैक्सीन - ROTAVAC5D लॉन्च किया है। वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

प्रश्न: ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1) यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई परियोजना है।

2) इसकी परियोजनाओं में तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के लिए वैश्विक बजट शामिल हैं वे तीन है - CO2, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड - और शहरी, क्षेत्रीय, संचयी और नकारात्मक उत्सर्जन में पूरक प्रयास

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

(a) केवल 1

(b) 2 ही

C.) दोनों 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (B)

यह 2001 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय को एक आम, पारस्परिक रूप से सहमत ज्ञान आधार स्थापित करने में मदद करने के लिए गठित किया गया है, जो वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि की दर को धीमा करने के लिए नीतिगत बहस और कार्रवाई का समर्थन करता है। यह फ्यूचर अर्थ का एक ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का रिसर्च पार्टनर है। इसकी परियोजनाओं में तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों - CO2, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड - और शहरी, क्षेत्रीय, संचयी और नकारात्मक उत्सर्जन में पूरक प्रयासों के लिए वैश्विक बजट शामिल हैं।

प्रश्न: हेरा मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें :

1) हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने हेरा के बजट को मंजूरी दी है।

2) इसका उद्देश्य डिडिमोस नामक क्षुद्रग्रह का पता लगाना है ।

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

a) केवल १

b) 2 ही

C.) दोनों 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (C)

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) का हेरा मिशन बाइनरी क्षुद्रग्रह - डिडिमोस जोड़ी का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बनकर एक नए रिकॉर्ड बनाने के लिए निर्धारित है। चांद की परिक्रमा करने वाले डिडिमोस, जिसे 'डिडीमून' कहा जाता है जो मिस्र में गीज़ा पिरामिड का आकार के लगभग है - इसका माप केवल 160 मीटर व्यास का है - यह अब तक का सबसे छोटा क्षुद्रग्रह होगा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) ने हेरा के बजट को मंजूरी दी है।

प्रश्न: सुगम्य भारत अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) अभियान का उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए एक बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना है

2) यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

3) सरकार ने हाल ही में अभियान की समय सीमा बढ़ा दी है क्योंकि लक्ष्य पूरा नहीं हुए हैं।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1

b) 1 और 3 ही

c) 3 ही

d) 1, 2 और 3

उत्तर : (बी) 1 और 3 केवल

सुगम्य भारत अभियान (AIC) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है। अभियान का उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए एक बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना है। इस अभियान में एक समावेशी समाज बनाने की दृष्टि है जिसमें विकलांग व्यक्तियों (PwD) के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार के सुगम्य भारत अभियान (AIC) की समय सीमा धीमी प्रगति के कारण मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है।

प्रश्न: चुनाव आयोग (EC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं ?

1) यह मान्यता प्राप्त दलों के किरच समूहों के बीच विवादों का निपटारा कर सकता है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

2) यह किसी चुनाव के परिणाम का स्वत: संज्ञान लेकर समीक्षा कर सकता है |

3) चुनाव आयोग के फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1

(B) 2 और 3 ही

(C) 1, 2 और 3

(D) केवल 1 और 2

उत्तर: A

राजनीतिक दलों को कानून के तहत चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत किया जाता है। आयोग समय-समय पर संगठनात्मक चुनाव कराने का आग्रह करके कामकाज में आंतरिक दल के लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। इसके साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा आम चुनावों में उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार मान्यता दी जाती है। आयोग, अपने अर्ध-न्यायिक क्षेत्राधिकार के एक हिस्से के रूप में, ऐसे मान्यता प्राप्त दलों के समूहों के बीच विवादों का भी निपटारा करता है। इसलिए कथन 1 सही है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

लंबे समय तक चलने वाले सम्मेलन और कई न्यायिक घोषणाओं द्वारा, एक बार चुनावों की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, न्यायपालिका चुनावों के वास्तविक आचरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। एक बार चुनाव पूरा होने और परिणाम घोषित होने के बाद, आयोग किसी भी परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकता है। यह केवल एक चुनाव याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से समीक्षा की जा सकती है, जिसे संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। कथन 2 सही नहीं है।

उपयुक्त याचिकाओं द्वारा आयोग के निर्णयों को उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव के संबंध में, ऐसी याचिकाएं केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

प्रश्न: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) यह NITI Aayog द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

2) यह फंड रिलीज पर नज़र रखने और उपयोग की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं ?

(A) केवल 1

(B) 2 ही

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

PFMS फंड प्रबंधन और कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के लिए ई-भुगतान के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन लेनदेन प्रणाली है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) प्रसंस्करण भुगतान, ट्रैकिंग, निगरानी, लेखांकन, सुलह और रिपोर्टिंग के लिए एक शुरू से अंत तक समाधान है। यह स्कीम प्रबंधकों को फंड रिलीज पर नज़र रखने और उनके अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इसलिए, कथन 2 सही है।

• यह पहले NITI Aayog के तहत था, लेकिन अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन शासन में विभिन्न हितधारकों के साथ ई-गवर्नेंस/ई शासन इंटरैक्शन है?

1) G2G (सरकार से सरकार)

2) जी 2 सी (नागरिकों के लिए सरकार)

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

3) जी 2 ई (नागरिको के लिए सरकार)

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1 और 2

(B) 2 और 3 ही

(C) 3 ही

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: D

ई-गवर्नेंस शासन में विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इन बातचीत को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है:

• G2G (सरकार से सरकार) - इस मामले में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल सरकारी संस्थाओं के कामकाज में शामिल सरकारी प्रक्रियाओं के पुनर्गठन के लिए, बल्कि विभिन्न संस्थाओं के भीतर और बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है।

• जी 2 सी (सरकार से नागरिक) - इस मामले में, सरकार और नागरिकों के बीच एक इंटरफेस बनाया जाता है जो नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला के कुशल वितरण से लाभान्वित करने में सक्षम बनाता है। यह एक ओर सार्वजनिक

सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाता है और दूसरी ओर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह नागरिकों को सरकार के साथ बातचीत करने का विकल्प देता है । प्राथमिक उद्देश्य सरकार को नागरिक-हितैषी बनाना है।

• G2B (सरकार से व्यवसाय) - यहां, ई-गवर्नेंस उपकरण का उपयोग व्यापार समुदाय - माल और सेवाओं के प्रदाताओं - सरकार के साथ निर्बाध बातचीत करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार के साथ काम करते समय लालफीताशाही में कटौती करना , समय की बचत करना, परिचालन लागत कम करना और अधिक पारदर्शी कारोबारी माहौल बनाना है। G2B पहल ट्रांजेक्शनल हो सकती है, जैसे कि लाइसेंसिंग, परमिट, खरीद और राजस्व संग्रह। वे प्रचार और सुविधावादी भी हो सकते हैं, जैसे कि व्यापार, पर्यटन और निवेश। ये उपाय व्यवसायों को अधिक कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए एक वातावरण प्रदान करने में मदद करते हैं।

• G2E (कर्मचारियों-सरकार) - सरकार अब तक की सबसे बड़ी नियोक्ता है और किसी भी संगठन की तरह , उसे अपने कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करनी होती है। यह सहभागिता संगठन और कर्मचारी के बीच एक दो-तरफ़ा प्रक्रिया है। आईसीटी उपकरणों का उपयोग एक तरफ इन बातचीत को तेज और कुशल बनाने में मदद करता है और दूसरी तरफ कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाता है।

प्रश्न: बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) यह एक वैधानिक निकाय है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

2) भारत का महान्यायवादी परिषद का पदेन सदस्य है।

3) यह भारत में कानूनी शिक्षा के लिए मानकों को पूरा करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं ?

(A) केवल 3

(B) 2 और 3 ही

(C) 1, 2 और 3

(D) केवल १

उत्तर: C

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) भारतीय बार को विनियमित करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसलिए, कथन 1 सही है।

इसके कार्य इस प्रकार हैं:

- अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को पूरा करना।
- अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा के लिए।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

o कानून सुधार को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना।

- कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना और कानूनी शिक्षा के मानकों को पूरा करना। इसलिए, कथन 3 सही है।
- ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनकी कानून में डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता होगी।
- गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल से चुने गए सदस्य होते हैं, और भारत के महान्यायवादी और भारत के सॉलिसिटर जनरल जो पदेन सदस्य होते हैं। इसलिए, कथन 2 सही है। स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों को पांच साल की अवधि के लिए चुना जाता है। परिषद अपने सदस्यों के बीच से दो साल की अवधि के लिए अपने स्वयं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।

प्रश्न: भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है?

1) ई-कॉमर्स

2) क्रिप्टोकरेंसी

3) अचल संपत्ति

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(A) केवल 1 और 2

(B) 1 और 3 ही

(C) 2 ही

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: ए

रियल एस्टेट विनियमन: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 - अचल संपत्ति क्षेत्र के नियमन और संवर्धन के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना और भूखंड की बिक्री, अपार्टमेंट के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम, जैसा भी मामला हो। अचल संपत्ति परियोजना में, एक कुशल और पारदर्शी तरीके से और अचल संपत्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए और शीघ्र विवाद निवारण के लिए एक सहायक तंत्र स्थापित करने के लिए और साथ ही रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण और सहायक अधिकारी के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों से प्राप्त अपील पर सुनने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना। ।

CRYPTOCURRENCY पंजीकरण: बिटकॉइन विनियमन को लागू करने में मुख्य समस्या यह है कि यह इस तरह के क्रिप्टोकरेंसी की प्राथमिक विशेषता के खिलाफ जाता है जो है गुमनामी। ब्लॉकचेन की संरचना, जो बिटकॉइन की रीढ़ है, केवल एक बेतरतीब ढंग से उत्पन्न पते और कुंजी को असाइन करके पार्टियों को शामिल करती है। इस प्रकार यह बिटकॉइन विनियमन को

मुश्किल बनाता है क्योंकि यह जानना संभव नहीं है कि लेनदेन में कौन शामिल है। आभासी मुद्राओं का प्रचलन जिसे डिजिटल / क्रिप्टो मुद्राओं के रूप में भी जाना जाता है, चिंता का कारण है। यह समय-समय पर विभिन्न मंचों पर व्यक्त किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बारे में बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह किया था।

ई-वाणिज्य विनियमन (ई-कॉमर्स रेगुलेशन): भारत में, तीन प्रकार के ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल हैं (i) ई-कॉमर्स का इन्वेंटरी आधारित मॉडल (ii) ई-कॉमर्स का मार्केटप्लेस आधारित मॉडल (iii) इन्वेंट्री के हाइब्रिड मॉडल और मार्केट प्लेस आधारित मॉडल। ई-कॉमर्स के लिए आईटी अधिनियम और डीआईपीपी दिशानिर्देश किसी भी प्राधिकरण के बिना ई-कॉमर्स क्षेत्र को विनियमित करते हैं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और ई-कॉमर्स: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देता है। ये पेपरलेस ट्रेडिंग की सुविधा के लिए कदम हैं। इस अधिनियम के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2000 भी हैं। आईटी संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 72 ए के तहत, एक वैध अनुबंध के उल्लंघन में सूचना के प्रकटीकरण की सजा निर्धारित है।

डीआईपीपी द्वारा ई-कॉमर्स के लिए एफडीआई दिशानिर्देश: डीआईपीपी ने ई-कॉमर्स में एफडीआई के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

भारत में बी 2 बी ई-कॉमर्स में 100% एफडीआई की अनुमति है|

बी 2 सी ई-कॉमर्स में किसी भी एफडीआई की अनुमति नहीं है| हालांकि, बी 2 सी ई-कॉमर्स में एफडीआई की अनुमति कुछ परिस्थितियों में डी गई है ।

ई- कॉमर्स में एफडीआई पर इन नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस आधारित मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है, जबकि ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं है। ई-कॉमर्स कई बहुपक्षीय वार्ता मंचों जैसे विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स आदि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारतीय पक्ष से ई-कॉमर्स पर इस तरह की वार्ता का नेतृत्व कर रहा है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की अयोग्यता के आधार हैं ?

1) यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है

2) यदि वह अपने पद के कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न है।

3) यदि वह भारत सरकार द्वारा किए गए किसी अनुबंध या समझौते से संबंधित या इच्छुक है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) केवल 1 और 2

(B) 1 और 3 ही

(C) 2 और 3 ही

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: D

दिए गए सभी कथन सही हैं।

राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कार्यालय से हटा सकते हैं:

(A) यदि वह दिवालिया हो गया है;

(B) यदि वह अपने पद के कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न है; या

(C) यदि वह राष्ट्रपति की राय में, मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है |

इसके अलावा, राष्ट्रपति दुर्व्यवहार के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भी हटा सकते हैं। हालांकि, इस मामले में, राष्ट्रपति को जांच के लिए मामले को उच्चतम न्यायालय में संदर्भित करना होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट, जांच के बाद,

हटाने का कारण बताता है और सलाह देता है, तो अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है। संविधान के प्रावधानों के तहत, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के दौरान , राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में दुर्व्यवहार 'शब्द को परिभाषित करते हुए, संविधान कहता है कि UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार का दोषी माना जाता है यदि वह (A) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा किए गए किसी अनुबंध से संबंधित या इच्छुक है

(B) किसी भी तरह से इस तरह के अनुबंध या समझौते के लाभ में या किसी सदस्य के रूप में अन्यथा किसी निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ आम तौर पर किसी भी तरह से लाभ में भाग लेता है।

प्रश्न: निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश एक साथ महासंघ रखने का उदाहरण हैं ?

1) स्पेन

2) यूएसए

3) भारत

4) बेल्जियम

विकल्प:

(A) केवल 2

(B) 1 और 2 केवल

(C) 1, 2 और 4 केवल

(D) 1, 3 और 4 केवल

उत्तर :D

व्याख्या : दो प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

पहले मार्ग में स्वतंत्र राज्यों का एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आना शामिल(coming together') है, ताकि संप्रभुता को और पहचान को बनाए रखते हुए वे अपनी सुरक्षा बढ़ा सकें। इस प्रकार के एक साथ आने वाले संघों में यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। संघों की इस पहली श्रेणी में, सभी घटक राज्यों में आम तौर पर समान शक्ति है |

दूसरा मार्ग वह है जहां एक बड़ा देश अपनी शक्ति को राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। भारत, स्पेन और बेल्जियम इस तरह के एक साथ महासंघों के निर्माण के उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी में, केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। महासंघ की अक्सर विभिन्न घटक इकाइयों में असमान शक्तियां होती हैं। (holding together' federation)

प्रश्न : भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार , जो निम्नलिखित विवरणों में से प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव आयोग को प्रदान करना है यदि वह चुनाव में लड़ने की इच्छा रखता है :

1) संपत्तियां और देनदारियां।

2) उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं ।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

3) शैक्षणिक योग्यता।

(A) 1 और 3

(B) 2 और 3

(C) केवल 2

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर :D

व्याख्या : भारत निर्वाचन आयोग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म के साथ एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा जिसमे विवरण होगा: -

□ पूर्व में उसके अपराधी तथ्यों की जानकरी ।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

 उसकी संपत्तियाँ और देनदारियाँ और वे

- उसके / उसके पति या पत्नी और आश्रितों, और

 उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि।

प्रश्न : प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ।

1) संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होती है।

2) प्रश्नकाल की कार्यप्रणाली कार्यपालिका को नियंत्रित करने और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की राय जानते हुए सत्तारूढ़ दल को उसकी कमियों के बारे में सचेत करने के लिए है ।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर :C

प्रश्न : भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है?

(A) भारत के समेकित कोष से सभी व्यय का लेखा- जोखा और रिपोर्ट करना ।

(B) आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सभी व्यय का लेखा- जोखा और रिपोर्ट करना ।

(C) सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों की ऑडिट और रिपोर्ट करने के लिए ।

(D) सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी राजस्व सरकारी खजाने में दर्ज है ।

उत्तर :D

प्रश्न : एसटी और एससी के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है :

(A) समाजवादी सिद्धांत

(B) गांधीवादी सिद्धांत

(C) अंबेडकर का सिद्धांत

(D) यह एक निर्देशक सिद्धांत नहीं है

उत्तर :C

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समेकित निधि (चार्ज व्यय) पर लगाया जाता है ?

1) राष्ट्रपति के परिलब्धियाँ और भत्ते ।

2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन ।

3) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन ।

4) ऋण जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है।

सही विकल्प चुनें।

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) 1, 2 और 4 केवल

(D) उपरोक्त सभी।

उत्तर :C

व्याख्या : भारत के समेकित कोष पर उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की केवल पेंशन का भार दिया जाता है। राज्यों के संबंधित समेकित धन पर वेतन और भत्ते का शुल्क भारित किया जाता है। ऋण ब्याज जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है भारत के समेकित निधि पर भारित किया जाता है।

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जाता है?

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

1) हैबियस कॉर्पस

2) मेंदेमस

3) निषेध

4) क्वो वारंटो

(A) 1, 2, 3

(B) 2, 3, 4

(C) 1, 2, 4

(D) 1, 2, 3, 4

उत्तर :B

व्याख्या : हैबियस कॉर्पस: याचिका को नजरबंद या गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना है, जैसा कि हैबियस कॉर्पस के अनुसार, कोई भी अन्य व्यक्ति हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से कर सकता है। यह रिट (लिखित याचिका) किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जारी की जा सकती है।

प्रश्न : निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र मौजूद हैं?

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

1) तमिलनाडु

2) केरल

3) गुजरात

4) हरियाणा

(A) सभी सत्य हैं

(B) 1 और 2 सत्य हैं

(C) केवल 3 सत्य है

(D) सभी असत्य हैं

उत्तर :C

व्याख्या : अनुसूचित क्षेत्र छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मौजूद हैं।

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

1) जिले का सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है।

2) जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

3) जिला जज के रूप में नियुक्ति के पात्र होने के लिए एक व्यक्ति सात साल या उससे अधिक से अधिवक्ता या एक वकील होना चाहिए, या संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में एक अधिकारी होना चाहिए ।

4) जब सेशन जज मौत की सजा सुनाते हैं, तो इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए ।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 और 2

(B) 2, 3 और 4

(C) 3 और 4

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर :D

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : जिला और सत्र न्यायालय एक जिले में आपराधिक न्यायालयों के पदानुक्रम के शीर्ष पर है। अनुच्छेद 233 में यह प्रावधान है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी और पात्रता के संबंध में, उन्हें सात वर्ष का एक वकील के रूप में अनुभव रहा होगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के अनुसार, जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड की घोषणा करता है, तो कार्यवाही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए और जब तक उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक सजा का निष्पादन नहीं किया जाएगा।

प्रश्न : लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है :

1) इसमें 22 सदस्य होते हैं (लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7)

2) इसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष है।

3) समिति के अध्यक्ष को इसके सदस्यों में से स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है।

4) कैग PAC के लिए मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है ।

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 1, 3 और 4

(C) केवल 1, 2 और 4

(D) उनमें से सभी

उत्तर :D

प्रश्न : संविधान की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है

(A) बिजली -----(i) समवर्ती सूची

(B) ड्रग्स और जहर ----(ii) समवर्ती सूची

(C) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा -----(iii) समवर्ती सूची

(D) कृषि ----- (iv) समवर्ती सूची

उत्तर :D

व्याख्या : कृषि और उससे संबंधित राज्य सूची में होते हैं।

प्रश्न : राष्ट्रपति शासन के दौरान (अनुच्छेद -356) इनमें से कौन सा सही नहीं है?

(A) भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने नियन्त्रण में ले सकते हैं ।

(B) भारत के राष्ट्रपति केवल राज्य विधायिका को निलंबित कर सकते हैं लेकिन सदन को भंग नहीं कर सकते ।

(C) भारत के राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश ला सकते हैं , यदि संसद सत्र में नहीं है।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(D) भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने में नहीं मान सकते ।

उत्तर :B

व्याख्या : भारत के राष्ट्रपति सदन को निलंबित या भंग कर सकते हैं।

प्रश्न : निम्न में से कौन सा कथन सही है हैं ?

1) 1948 में, भारत सरकार ने फ़ैज़ल अली की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की ।

2) 1953 में, एसके धर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था ।

3) स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था ।

4) वर्तमान में, दस मौलिक कर्तव्य हैं।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

कोड:

(A) 1 और 2

(B) 3 और 4

(C) केवल 3

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर :C

व्याख्या : भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, मुख्य रूप से दक्षिण भारत से मांग थी। नतीजतन, जून 1948 में, भारत सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के आयोजन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए S.K.Dhar की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

भाषाई कारक के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, सभी रुकावतें आसान हो गए। अन्य क्षेत्रों ने भी भाषाई कारक के आधार पर अलग राज्यों के निर्माण की मांग शुरू कर दी। भारी दबाव ने भारत सरकार को राज्यों के अलगाव के भाषाई आधार पर विचार किया जा सकता है या नहीं, इस पूरे सवाल पर जानने के लिए एक नया आयोग बनाने के लिए मजबूर किया। इसने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया।

प्रश्न : निम्न में से कौन सा कथन सही है हैं?

1) भारतीय संघ की इकाइयों के क्षेत्र को संसद द्वारा एक साधारण बहुमत से बदल दिया जा सकता है ।

2) एक राज्य विधायिका की सहमति संसद द्वारा उसके क्षेत्र को पुनर्वितरित करने से पहले आवश्यक है ।

3) किसी भी राज्य के पुनर्वितरण क्षेत्र पर संसद में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है ।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

4) राष्ट्रपति को राज्य का नाम बदलने हेतु विधेयक की सिफारिश करने से पहले राज्य की राय प्राप्त करनी चाहिए ।

कोड:

(A) केवल 1

(B) 2 और 4

(C) 2,3 और 4

(D) 1 और 3

उत्तर :D

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश होने से पहले राष्ट्रपति राज्य की राय लेंगे। वह राज्य की राय से बाध्य नहीं है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से राय लेनी है।

प्रश्न : उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।

2) उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद चुनाव आयोग को संदर्भित किया जाता है ।

दिए गए कथनों में से कौन सा सही हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर :A

व्याख्या : संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

प्रश्न : परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1) परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

2) जब परिसीमन आयोग के आदेश लोक सभा या राज्य विधान सभा के सामने रखे जाते हैं, तो वे आदेशों में किसी भी संशोधन को नहीं कर सकते हैं ।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है हैं ?

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर :C

व्याख्या : परिसीमन आयोग एक वैधानिक निकाय है जो परिसीमन आयोग अधिनियम, 1972 के तहत गठित किया गया है। परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

प्रश्न : निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित कोष से राज्यों को राजस्व के अनुदान में सहायता के सिद्धांतों की सिफारिश करता है?

(A) वित्त आयोग

(B) अंतर-राज्य परिषद

(C) केंद्रीय वित्त मंत्रालय

(डी) लोक लेखा समिति

उत्तर :A

व्याख्या : भारत के समेकित कोष से राज्य के राजस्व की सहायता में अनुदान देने वाले सिद्धांतों की सिफारिश वित्त आयोग द्वारा की जाती है।

प्रश्न : निम्न में से कौन-सा कथन अंतर-राज्य परिषद के बारे में सही है हैं?

1) यह संघ के राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक स्थायी संवैधानिक निकाय है ।

2) प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है ।

3) केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिनके पास विधानसभाएं नहीं हैं , उन्हें परिषद के सदस्य के रूप में नहीं माना जाता है।

(A) केवल 1

(B) 1 और 3

(C) केवल 2

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर :C

व्याख्या : अंतर-राज्य परिषद संघ के राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। इसे 'किसी भी समय' स्थापित किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि इस तरह की परिषद की स्थापना से जनता के हितों की सेवा की जाएगी। प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

सदस्य:

1. कैबिनेट स्तर के केन्द्रीय मंत्रियों को प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है।

2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।

3. केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों जिसके पास विधान सभा और जिसके पास विधान सभा नहीं है वहन के संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को ।

प्रश्न : एक साथ चुनावों की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

1) यह सरकारों को शासन के लिए चार साल समर्पित करने की अनुमति देता है।

2) लगातार चुनावों के भारी आर्थिक बोझ को कम करें ।

3) एक साथ चुनाव की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 174 का उल्लंघन कर सकती है ।

इनमें से कौन सा सही है हैं?

(A) केवल 1

(B) 2 और 3

(C) 1 और 2

(D) उपरोक्त सभी।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उत्तर :D

व्याख्या : साथ-साथ चुनाव सरकारों को शासन के लिए चार साल समर्पित करने की अनुमति देता है।

यदि चुनाव लगातार होते है तो चुनाव जीतना सभी राजनेताओं की पहली प्राथमिकता बन जाती है।

अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 174 के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव दोनों में से किसी एक को भंग करने के छह महीने (क्रमशः) के भीतर होने चाहिए। यह संभव नहीं है, यदि चुनाव केवल निश्चित अवधि के चुनाव हों। इससे अगर चुनाव छह महीने के भीतर नहीं होते हैं, तो यह लोकतंत्र में एक भटकाव की स्थिति बन सकती है ।

प्रश्न : दुनिया भर में मतदान का अधिकार पाने के लिए महिलाओं ने बहुत लंबा संघर्ष किया है।

इस संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है ?

1) दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मतदान का अधिकार पाने के लिए महिलाओं के संघर्ष को बल मिला ।

2) इसी महिलाओं के आंदोलनों को महिलाओं के मताधिकार आंदोलन के रूप में जाना जाता था।

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

3) 1920 के दशक में महिलाओं को यूनाइटेड किंगडम में पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था ।

कोड:

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 3

उत्तर :B

व्याख्या : महिलाओं को मतदान के अधिकार के आंदोलन को मताधिकार आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं के वोट के संघर्ष को बल मिला। 1920 में अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, जबकि ब्रिटेन में महिलाओं को कुछ साल बाद 1928 में उसी तरह वोट देने का अधिकार मिला जैसा कि पुरुषों को मिला था।

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) राज्यसभा मुख्य रूप से लोक सभा द्वारा शुरू की गई हानि की समीक्षा करने और उसे बदलने के लिए नहीं है |

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

2) राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाना चाहिए, इसमें वे सदस्य शामिल होते हैं जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं ।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है हैं ?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर :B

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : राज्यसभा धन विधेयक को छोड़कर लोक सभा द्वारा शुरू की गई हानि की समीक्षा करने और उसमें बदलाव कर सकती है।

प्रश्न : निम्न में से कौन-सी स्थितियाँ क्वो वारंट के रिट जारी करने के लिए आवश्यक हैं?

1) कार्यालय को सार्वजनिक होना चाहिए और एक क़ानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए ।

2) कार्यालय में एक दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए, न कि किसी दुसरे सेवक की इच्छा और दूसरे के प्रसादपर्यंत के दौरान कार्य करना।

3) ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने के लिए एक क़ानून या वैधानिक साधन में संविधान का उल्लंघन हुआ है ।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें :

(A) 1 और 2

(B) 1 और 3

(C) 2 और 3

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर :D

व्याख्या : क्यो वारंटो की रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं:

(i) कार्यालय को सार्वजनिक होना चाहिए ।

(ii) ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने पर संविधान या एक क़ानून या वैधानिक उपकरण का उल्लंघन हुआ है।

क्यो वारंटो की कार्यवाही का मूल आधार यह है कि जनता को यह देखने की रूचि है कि एक गैरकानूनी दावेदार सार्वजनिक कार्यालय नहीं है।

प्रश्न : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत , मानव तस्करी में निम्नलिखित में से कौन शामिल है ?

1) पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सामान की तरह बेचना और खरीदना ।

2) वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों का अनैतिक तस्करी

3) देवदासियाँ

4) गुलामी

(A) केवल 1,2 और 3

(B) केवल 2,3 और 4

(C) केवल 1,3 और 4

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर :D

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

व्याख्या : कृत्यों को दंडित करने के लिए, संसद ने अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 बनाया है।

नोट: तेलंगाना की देवदासी के हालिया मामले का अध्ययन अवश्य करें |

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत 42 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ?

1) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करने के लिए (अनुच्छेद 39)।

2) पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा के लिए (अनुच्छेद 48 (A)

3) सहकारी समितियों 8a का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए (अनुच्छेद 43B)

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 2

(D) उनमें से सभी

उत्तर :C

व्याख्या : 1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में चार नए निर्देश सिद्धांत जोड़े।

1. बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए (अनुच्छेद 39)।

2. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 ए)।

3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 ए)।

4. पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए (अनुच्छेद 48 ए)।

प्रश्न : " भारतीय संविधान की मूक विशेषताओं " के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें :

IAStopper.com
an institute of your dreams

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

1) अधिकांश प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से उधार लिया गया था ।

2) इसे विस्तार से समझाया गया है अन्यथा नए लोकतंत्र को खतरे में डाला जा सकता है।

3) संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निरपेक्ष है।

4) यह पूरे देश के लिए एक एकल संविधान है।

उपरोक्त में से कौन गलत हैं?

(A) 1,2 और 3

(B) 1 और 4

(C) 3 और 4

(D) 1 और 3

उत्तर :C

व्याख्या : शक्तियों का विभाजन निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि समवर्ती सूची मौजूद है।

प्रश्न : न्यायिक समीक्षा के साधनों के संबंध में गंभीरता के सिद्धांत की वकालत की गई है-

(A) सुप्रीम कोर्ट कानून के आपत्तिजनक भागों के लिए नए प्रावधानों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बना सकता है।

(B) सुप्रीम कोर्ट को पूरे कानून को शून्य घोषित करना होगा , भले ही कानून के कुछ हिस्से संविधान में उल्लंघन करते हों

(C) सुप्रीम कोर्ट कानून के केवल ऐसे हिस्से को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

EKLAVYA 360°PRELIMS PROGRAM – TEST 2 व्याख्या

उत्तर :C

प्रश्न : सशस्त्र बलों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें :

1) अनुच्छेद 136 (2) और 227 (4) मार्शल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को बाहर करता है ।

2) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट मार्शल के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

3) सशस्त्र बलों के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की अनुमति नहीं है ।

गलत विकल्प का चयन करें:

(A) 1 और 2

(B) 2 और 3

(C) 1 और 3

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर :B

व्याख्या : अनुच्छेद 136 (2) और 227 (4) कोर्ट मार्शल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को बाहर करता है। लेकिन एक ही समय में, वे अनुच्छेद 32 और 226 (सर्वोच्च और उच्च न्यायालय) की शक्तियां जारी करने के अधिकार के संचालन को बाहर नहीं करते हैं।